ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

विकास की मुख्य धारा में आएं आदिवासी -प्रो करमा उरांव

हिंदी विश्वविद्यालय में 'मध्यभारत के आदिवासी : समस्याएं एवं संभावनाए' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उदघाटन, मानवविज्ञान विभाग का आयोजन

बीज वक्तव्य देते हुए डॉ. करमा उरांव। मंच पर दाएं से वित्ताधिकारी संजय भास्कर गवई, डॉ. जोसेफ बारा, प्रो. मनोज कुमार, प्रो. फरहद मलिक तथा डॉ. प्रीति सागर।

स्मारिका एवं शोध संक्षेपिका का प्रकाशन करते हुए दाएं से संजय भास्कर गवई, डॉ. जोसेफ बारा, प्रो. मनोज कुमार, डॉ. करमा उरांव तथा प्रो. फरहद मलिक।

राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित मानवविज्ञानी, शोधार्थी तथा छात्र-छात्राएं।

आदिवासी समाज के विकास के लिए सामाजिक –राजकीय व्यवस्था को कारगर बनाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। आदिवासियों का इतिहास और पृष्ठभूमि को देखा जाए तो उनकी कुर्बानियां और आंदोलन देखने को मिलते है। उनकी कुर्बानियां और आंदोलनों के बुनियादी उद्देश्य भी सामने आते है। आज आदिवासी मुख्य धारा में तो है परंतु भटकाव की वजह से विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। उक्त उदबोधन रांची विश्वविद्यालय, रांची के मानवविज्ञान विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉ. करमा उरांव ने दिए। वे वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आयोजित दो-दिवसीय (19-20) राष्ट्रीय संगोष्ठी के उदघाटन के अवसर पर बीज वक्तव्य दे रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के संस्कृति विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रो. मनोज कुमार ने की।

विश्वविद्यालय में मानवविज्ञान विभाग द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा भारतीय मानविज्ञान सर्वेक्षण के संयुक्त तत्वावधान में 'मध्य भारत के आदिवासी – समस्याएं एवं संभावनाएं' विषय पर आयोजित संगोष्ठी का उदघाटन विवि के हबीब तनवीर सभागार में सोमवार को किया गया। इस अवसर पर मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के प्रो. जोसेफ बारा, विश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी संजय भास्कर गवई तथ मानवविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो. फरहद मलिक उपस्थित थे।

अपने बीज वक्तव्य में डॉ. उरांव ने कहा कि झारखंड राज्य में 32 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में 31 जनजातियां है, उडीसा और बंगाल जैसे अन्य राज्यों में भी जनजातियों की उपस्थिति हैं। उनकी गतिविधियां, सामाजिक-सांस्कृतिक क्रियाकलाप तो एक है परंतु राजनैतिक सीमाओं की वजह से वे अलग हुए हैं। ऐसे में सरकारी योजना तैयार करने समय चुनौतियां पेश आती है। हमें चाहिए कि उनके सामाजिक-राजनैतिक सेटअप को कारगर बनाया जाए, ताकि उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। आदिवासी और भाषा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा उनकी ही भाषा में दी जानी चाहिए और संस्कृति तथा आचार-व्यवहार की बातें पाठ्यक्रमों में शामिल की जानी चाहिए। आदिवासी धारणाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अबुजमाड़ क्षेत्र के लोग दुध पिना वर्ज्य मानते है। इस प्रकार की धारणाओं को दूर करने के लिए कारगर अभियान चलाने की बात डॉ. उरांव ने रखी। उन्होंने झारखंड, उडीसा, छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र की गोंडी जनजातियों का उल्लेख करते हुए सूझाव दिया कि उनके धर्म और संस्कृति का कोडिफाइंग किया जाए।

मुख्य वक्ता डॉ. जोसेफ बारा ने आदिवासी शिक्षा की स्थिति पर अपनी बात रखी। सर्वेक्षणों के हवाले से उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में शिक्षा की स्थिति आज भी गंभीर बनी हुई है। सन 2008 में विद्यार्थियों का ड्राप आउट रेट 62.45 प्रतिशत था। बोर्ड की परीक्षा में 50 प्रतिशत बच्चे फेल होते है और केवल 1.94 विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। उन्होंने आदिवासी और आधुनिक शिक्षा में तालमेल बिठाने की बात अपने वक्तव्य में रखी।

अध्यक्षीय वक्तव्य में प्रो. मनोज कुमार ने कहा कि शिक्षा ही विकास का महत्वपूर्ण और अहम मापदंड है और आदिवासी समाज को शिक्षा के साथ ही विकास के पथ पर लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विकास के दबाओं के चलते आदिवासी को विस्थापित किया जा रहा है, उनके सामाजिक-सांस्कृतिक स्रोत नष्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में हमें विकास केंद्रित पाठयक्रमों के माध्यम से आदिवासी समाज के विकास की दिशा में पहल करनी चाहिए।

राष्ट्रीय कार्यशाला की प्रस्तावना रखते हुए मानवविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो. फरहद मलिक ने कहा कि कुलपति विभूति नारायण राय के संरक्षण में तथा तत्कालिन प्रतिकुलपति प्रो. नदीम हसनैन के नेतृत्व में 17 सितंबर 2009 को विश्वविद्यालय में मानवविज्ञान विभाग की शुरूआत हुई। मानवविज्ञान का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र जनजातीय समुदाय है इसलिए विदर्भ क्षेत्र में स्थित यह विभाग जनजातीय समुदाय पर महत्वपूर्ण अध्ययन कर रहा है, जिसमें विदर्भ क्षेत्र की बहुरंगी जनजातीय

सांस्कृति मुख्य रूप से शामिल है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन इसी दिशा में की गयी एक शसक्त पहल है। उन्होंने कहा कि दो दिनों में की गयी चर्चा के आधार पर एक समग्र रिपोर्ट केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजी जाएगी, जिसमें संगोष्ठी में प्रस्तुत सिफारिसों पर ध्यान देने का आग्रह मंत्रालय से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी में 100 से भी अधिक शोधपत्र प्राप्त हुए हैं और अधिकतर शोधपत्र युवा शोधार्थियों द्वारा भेजे गये हैं। इस अवसर पर स्मारिका एवं शोध संक्षेपिका का प्रकाशन मंचासीन अतिथियों के द्वारा किया गया। समारोह का संचालन साहित्य विद्यापीठ में असोशिएट प्रोफेसर डा. प्रीति सागर ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन वित्ताधिकारी संजय गवई ने किया। इस अवसर पर देशभर से आए मानवविज्ञानी, शोधार्थी तथा छात्र-छात्राएं बडी संख्या में उपस्थित थे।

विकास के केंद्र में राज्य नहीं गांव हों -डॉ. बी. डी. शर्मा

‘भारत के आदिवासी क्षेत्र में स्वायत्त व्यवस्था किसकी’ विषय पर विशेष व्याख्यान

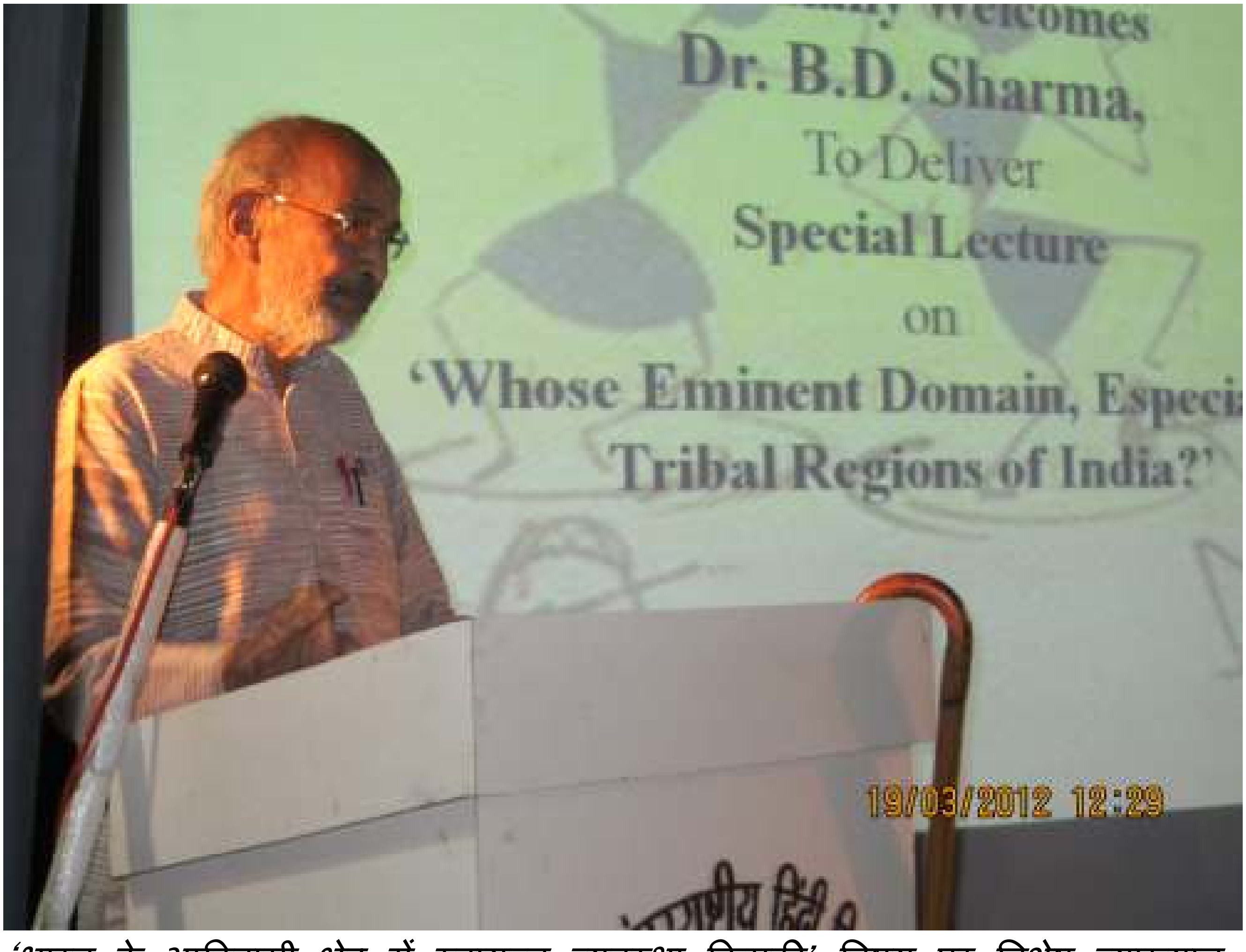

‘भारत के आदिवासी क्षेत्र में स्वायत्त व्यवस्था किसकी’ विषय पर विशेष व्याख्यान देते हुए डॉ. बी. डी. शर्मा।

औद्योगिक विकास की आंधी में आदिवासी जल, जंगल और जमीन से बेदखल किए जा रहे हैं। उन्हें विकास में बाधक माने जाने लगा है। उन्हें अनवांटेड करार दिया जा रहा है। आदिवासी समाज के विकास के लिए हमें चाहिए कि उनके विकास के केंद्र में राज्य न होकर गांव हो। उक्त मंतव्य जाने-माने मानवविज्ञानी डॉ. बी.डी. शर्मा ने दिये। वे वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आयोजित दो-दिवसीय (19-20 मार्च) राष्ट्रीय संगोष्ठी के उदघाटन के अवसर पर विशेष व्याख्यान में बोल रहे थे। उनके व्याख्यान का विषय था 'भारत के आदिवासी क्षेत्र में स्वायत्त व्यवस्था किसकी'।

विश्वविद्यालय में मानवविज्ञान विभाग द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के संयुक्त तत्वावधान में 'मध्य भारत के आदिवासी – समस्याएं एवं संभावनाएं' विषय पर आयोजित संगोष्ठी के उदघाटन के बाद विशेष व्याख्यान में डॉ. शर्मा ने कहा कि आदिवासी समुदाय के विकास के लिए सरकार धन मुहैया कराती है परंतु यह धन आदिवासी समुदाय तक नहीं पहूंच पाता। देश में किसी भी बड़ी परियोजना में सर्वप्रथम आदिवासी ही प्रभावित होते है और उन्हें उस क्षेत्र से हटाया जाता है। किसी विशेष परियोजना में कितने आदिवासी विस्थापित हुए इसका रिकार्ड भी नहीं मिल पाता है। जहां पर आदिवासी के अधिकार क्षेत्र हैं उस क्षेत्र को मानने के लिए राज्य तैयार ही नहीं है। कुछ साल पूर्व आदिवासी उप-योजना बनी थी उसमें शोषण की समाप्ति की बात कही गयी थी। परंतु अभी भी शोषण से मुक्ति नहीं मिली है। संविधान के आर्टिकल 40 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य पंचायतों को अधिकार देगा परंतु यह उचित नहीं है। विकास के केंद्र में गांव को ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। अपने विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य में डॉ. शर्मा ने आजादी से पूर्व की स्वायत्त व्यवस्था से लेकर अब तक की व्यवस्था पर अपनी बात रखी।

हिंदी विवि शोध एवं विकास का मानक केंद्र बनेगा –प्रो. ए. अरविंदाक्षन

‘मध्यभारत के आदिवासी : समस्याएं एवं संभावनाए’ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन

संगोष्ठी के समापन पर अध्यक्षीय उदबोधन देते हुए प्रतिकुलपति प्रो. ए. अरविंदाक्षन

संगोष्ठी के समापन समारोह में उपस्थित मानवविज्ञानी, प्रतिभागी तथा छात्र-छात्राएं

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रो. ए. अरविंदाक्षन ने विश्वविद्यालय में मानवविज्ञान विभाग द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा भारतीय मानविज्ञान सर्वेक्षण, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में 'मध्य भारत के आदिवासी–समस्याएं एवं संभावनाएं' विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिंदी विश्वविद्यालय मध्य भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के लिए शोध एवं विकास का मानक केंद्र बनेगा। 12वीं पंचवर्षिय योजना के लिए तैयार किये गये प्रस्ताव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में आगामी वर्षों में पर्यावरण अध्ययन केंद्र, निरंतर विकास केंद्र और विलुप्त होने वाली भाषाओं के लिए अध्ययन केंद्र के रूप में तीन केंद्र खोले जाएंगे जिससे विश्वविद्यालय शोध की दिशा में और आगे बढ़ेगा।

विवि के हबीब तनवीर सभागार में उक्त संगोष्ठी का समापन हुआ। इस अवसर पर मानव विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो. फरहद मलिक, प्रो. बी. एम. मुखर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर निशीथ राय तथा साहित्य विद्यापीठ की रीडर डॉ. प्रीति सागर मंचस्थ थे।

प्रो. अरविंदाक्षन ने कहा कि विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनेक प्रस्ताव भेजने की तैयारी की है। यदि हमारे प्रस्तावों को मान्यता मिलती है तो आगामी वर्षों में विश्वविद्यालय में विभिन्न केंद्र शुरू हो जाएंगे। अर्थशास्त्र, समाजविज्ञान और कृषि जैसे विषयों को लेकर भी हम अध्ययन और अध्यापन का

कार्य शुरू करना चाहते हैं। समापन के अवसर पर प्रतिकुलपति द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किये गये।

प्रारंभ में प्रशांत खत्री ने संगोष्ठी की रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रो. बी. एम. मुखर्जी ने अपने वक्तव्य में आदिवासी समाज के विकास के नीति निर्धारक घटकों पर अपनी बात रखी। समस्त संगोष्ठी में उभरे विचारों पर एक अनुशंसा पत्र तैयार किया गया जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के डॉ. विजय पी. शर्मा ने प्रस्तुत किया। यह पत्र भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के मानवविज्ञान विभाग के प्रो. पी. सी. जोशी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में राजीव गांधी चेअर के अध्यक्ष प्रो. एस. एन. चौधरी तथा रांची विश्वविद्यालय के डॉ. प्रभाकर के. सिंह ने प्रतिभागियों के रूप में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। समारोह का संचालन डॉ. प्रीति सागर ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन मानव विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर निशीथ राय ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर देशभर से आए मानवविज्ञानी, शोधार्थी तथा छात्र-छात्राएं बडी संख्या में उपस्थित थे।

आदिवासी समुदाय के समग्र विकास हेतु
भारत सरकार के जनजातिय कार्य मंत्रालय को भेजी जाने वाली अनुशंसा

अनुशंसा पत्र प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के डॉ. विजय पी. शर्मा

समापन *सत्र के अवसर पर अनुशंसा पत्र तैयार किया गया जिसे भारत सरकार के जनजातिय कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा। अनुशंसा में कहा गया है कि आदिवासी समुदाय से संबंधित योजनओं को फलीभूत बनाने के लिए राष्ट्रीय संकल्प पत्र जारी किया जाए। आदिवासी इलाकों के युवाओं के भटाकाव को रोकने हेतु उन क्षेत्र की विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने का कार्य किया जाए। क्षेत्रवार जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बनाई जाए एवं उन्हें नयी 'युद्धशैली' के रूप में लागू किया जाए। आदिवासी क्षेत्र में कृषि के लिए जलसंसाधन प्रबंधन का उपाय किया जाना चाहिए साथ ही कृषि को उत्पादनशील बनाने का प्रयास चेक डैम एवं लिफ्ट एरिगेशन को बढ़ावा देकर किया जाए। महिला एवं युवाओं को बृहद व्यापार समूहों में जोड़कर आगे बढ़ाया जाए। जनजातियों को अपनी भाषा में ही प्राथमिक शिक्षा दी जाए। राष्ट्रीय विकास की योजनाओं में क्षेत्रीय संप्रभुता ध्यान में रखी जाए तथा उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। स्वास्थ्य को लेकर मूल्यांकन हेतु एक सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं की संयुक्त समिति बनाई जाए। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन कोर्स चलाए जाएं। केंद्र सरकार के पास विलंबित जनजातिय पॉलिसी को भारतीय संसद द्वारा शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत किया जाना चाहिए। उक्त अनुशंसा पर अमल करने का आग्रह इस संगोष्ठी के माध्यम से भारत सरकार को किया गया है।*

बी. एस. मिरगे

जनसंपर्क अधिकारी